दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय उद्घोषित: 18.11.2013

मू.वि.या. 1112/2013

इंदु परियोजना लिमिटेड ..... याचिकाकर्ता

बनाम

भारत का संघ ..... प्रत्यर्थी

इस मामले में पेश हुए अधिवक्ता:

याचिकाकर्ता के लिए: श्री सीए सुंदरम व श्री अशोक भान, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आशीष भान व सुश्री गिन्नी राठत्रे, अधिवक्तागण

प्रत्यर्थी के लिए: श्री राजीव मेहरा, ए. एस. जी. श्री सुमित पुष्करना, सी. जी. एस. सी. व श्री जसविंदर सिंह व सुश्री सारा सुंदरम, अधिवक्तागण

कोरम:

माननीय न्यायाधीश श्री राजीव शकधर

श्री राजीव शकधर,न्या.

अं.अ.सं. 18122/2013 (छूट)

केवल अपवादों के अधीन अनुमति दी गई

मू.वि.या. सं. 1112/2013

1. यह मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 9 के तहत दायर याचिका है, जिसमें हैदराबाद स्थित आईडीबीआई बैंक की संबंधित शाखा द्वारा जारी 6,76,69,100/- रुपये की राशि की निष्पादन बैंक गारंटी, जिसका दिनांक 25.10.2010 का संख्या 2010133IBGP0326 है, के नकदीकरण के संबंध में व्यादेश की मांग की गई है।

1.1. मैं शुरू में ही यह नोट करना चाहूंगा कि याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 9 के तहत एक बार फिर एक याचिका दायर की थी, जिसमें समान दलीलें दी गई थीं, हालांकि यह एक अलग अनुबंध से संबंधित थी। इस याचिका में भी, उस मामले में बैंक गारंटी को लागू करने पर निषेधाज्ञा मांगी गई थी। उक्त याचिका को **मू.वि.या.**1097/2013 के रूप में क्रमांकित किया गया था। 01.11.2013 के निर्णय द्वारा याचिका को खारिज कर दिया गया था। मुझे सूचित किया गया है कि डिवीजन बेंच के समक्ष एक अपील पेश की गई थी, जो निष्फल हो गई थी, क्योंकि अपील के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी ने बैंक गारंटी को भुना लिया था।

1.2. यह याचिका, व्यापक रूप से, ओ. एम. पी. सं. 1097/2013 में निर्णय देते समय मेरे द्वारा ली गई और निपटाई गई याचिकाओं की पुनरावृत्ति है। इस प्रकार यह याचिका धनुष की दूसरी डोर की तरह है। यह कहने के बाद, कोई भी इस बात को ध्यान में रखे बिना नहीं रह सकता है कि इस तरह के विवादों पर बार-बार निर्णय लेने में लगने वाला समय और खर्च बहुत अधिक है।

1.3 जैसा कि मैंने 14.08.2013 को **मू.वि.या.** संख्या 742/2013 में पारित अपने निर्णय में बताया था, जिसका शीर्षक था ***डीएससी लिमिटेड बनाम रेल विकास निगम लिमिटेड और अन्य***, ऐसा प्रतीत होता है कि अधिवक्ता याचीगण को इस विषय पर कानून की स्थिति के बारे में मार्गदर्शन करने में असमर्थ हैं। ऐसी याचिकाओं को बार-बार दायर किए जाने का एक कारण शायद यह है कि देश की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून को बहुत अच्छी तरह से तय किए गए मुद्दों के संबंध में भारी लागत नहीं लगाने में न्यायालयों द्वारा दिखाई गई हिचकिचाहट है। जो बात मामले को और भी बदतर बनाती है वह यह है कि वर्तमान याचिका के साथ तीन अन्य याचिकाएँ हैं, और शायद, कई अन्य याचिकाएं विचाराधीन हैं।

2. इसलिए, बिना किसी देरी के, मैं वर्तमान याचिका में मौजूद तथ्यों और उन तर्कों के समर्थन में दिए गए तर्कों पर ध्यान देना चाहता हूँ। हालाँकि, मैं शुरू में ही यह बताना चाहता हूँ कि याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए श्री सुंदरम ने मुझे स्पष्ट रूप से बताया कि मुख्य मामले में की गई प्रस्तुतियाँ मुख्य याचिका के साथ दायर की गई अन्य तीन याचिकाओं को कवर करेंगी।

2.1 हालांकि, अच्छी व्यवस्था के लिए, मैंने अलग-अलग आदेश पारित किए हैं, ताकि प्रत्येक मामले में प्राप्त होने वाली तिथियों और घटनाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सके; हालाँकि, प्रस्तुत की गई चर्चा सामान्य है।

3. 15.06.2010 को प्रत्यर्थी ने "उधमपुर (सेना) और उधमपुर (वायुसेना) पैकेज-I बी में आवासीय आवास का निर्माण" (मुद्दे में कार्य) के रूप में वर्णित कार्य के निष्पादन के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) जारी की।

3.1 चूंकि याचिकाकर्ता को सफल बोली लगाने वाला घोषित किया गया था, इसलिए उसके पक्ष में दिनांक 30.09.2010 को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया था। जारी किए गए कार्य का कुल मूल्य 135.17 करोड़ रुपये आंका गया था। अनुबंध की कुल अवधि साइट सौंपे जाने की तिथि से 27 महीने थी; जैसा कि याचिका में कहा गया है। कार्य को पांच चरणों में निष्पादित किया जाना था। कार्य शुरू होने की तिथि 09.10.2010 थी। इसलिए, अनुबंध को 08.01.2013 को या उससे पहले पूरा किया जाना आवश्यक था।

3.2 अनुबंध की शर्तों के अनुसार याचिकाकर्ता को अनुबंध मूल्य के 5% के बराबर एक निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी थी। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने 25.10.2010 को 6,76,69,100/- रुपये के मूल्य की एक निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता के अनुसार बैंक गारंटी 31.12.2014 तक वैध है।

3.3 याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान 08.12.2010 को किया गया, जो कि लगभग ढाई महीने की देरी के बाद हुआ। याचिकाकर्ता का कहना है कि मोबिलाइजेशन अग्रिम के विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा 08.02.2011 से 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वसूली शुरू की गई थी। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि कार्य के निष्पादन को शुरू करने के लिए

उसने संबंधित साइट पर संसाधन जुटाए थे। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने संबंधित कार्य के निष्पादन को सक्षम करने के लिए कई लाख रुपये की लागत से मचान बनवाया था।

3.4 याचिकाकर्ता का दावा है कि अनुबंध की शर्तों के विपरीत, जारी की गई साइट को उसे टुकड़ों में सौंपा गया था, जिसके परिणामस्वरूप, अन्य बातों के साथ-साथ, काम के निष्पादन में देरी हुई।

3.5 याचिका में कई अन्य कारण भी बताए गए हैं, जिनके कारण याचिकाकर्ता के अनुसार, मुद्दे में काम के निष्पादन में बाधा उत्पन्न हुई। ये कारण इस प्रकार हैं: भारी और अप्रत्याशित बारिश की शुरुआत; छेत्री एन्क्लेव में पांच ब्लॉकों में मौजूदा पानी की पाइपलाइनों को हटाने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा लिए गए निर्णय में देरी; सार्वजनिक बंद की शुरुआत; और स्टील की अनुपलब्धता, जिसे अनुमोदित विक्रेताओं यानी सेल(एसएआईएल) से प्राप्त किया जाना था।

3.6 यह भी माना जाता है कि याचिकाकर्ता ने दिसंबर, 2013 तक समय बढ़ाने के लिए आवेदन किया है, जो प्रत्यर्थी के विचार के लिए लंबित है।

4. इसी पृष्ठभूमि में, जब याचिकाकर्ता को 08.08.2013 को पता चला कि प्रतिवादी ने 07.08.2013 के पत्र के माध्यम से बैंक गारंटी को लागू करने की मांग की है, तो उसने अधिनियम की धारा 9 के तहत एक याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया; जिसे मू.वि.या. संख्या 783/2013 के

रूप में क्रमांकित किया गया था। 12.08.2013 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता के पक्ष में एक अंतरिम व्यादेश दी गई थी, इस कारण से कि प्रथम दृष्टया, उस स्तर पर इसे लागू किया जाना, बैंक गारंटी की शर्तों के अनुरूप नहीं लग रहा था। प्रत्यर्थी ने, स्पष्ट तौर पर, अपने लागू करने के पत्र में इस दोष को पूरा करने के लिए 23.10.2013 के एक नए लागू करने के पत्र के साथ पहले के लागू करने के पत्र को अध्यारोही कर दिया।

4.1. याचिकाकर्ता ने वास्तव में 23.10.2013 के पत्र द्वारा किए गए नए गारंटी को लागू करने पर आपत्ति जताई है।

4.2. दिनांक 31.10.2013 के आदेश के तहत, **मू.वि.या.** संख्या 783/2013 का निपटान किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता को दिनांक 23.10.2013 के पत्र को, यद्यपि कानून के अनुसार, चुनौती देने की स्वतंत्रता दी गई;

5. इस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुंदरम ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं:

(i) यह लागू करने की कार्यवाही बैंक गारंटी के संदर्भ में नहीं थी क्योंकि इसमें यह नहीं कहा गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कथित उल्लंघन के कारण नुकसान हुआ था। दूसरे शब्दों में, नुकसान का तथ्य, (गारंटी) लागू करने के पत्र में व्यक्त नहीं किया गया था। इस संबंध में, उन्होंने अनुबंध की

सामान्य शर्तों (जी.सी.सी.) के खंड 47 और 48 के प्रावधानों और खंड 60 के पहले परंतुक का उल्लेख किया।

(ii) जबकि, यह संबंधित बैंक, जिसने बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी, की ज़िम्मेदारी नहीं थी कि वह इस बात की जांच करे कि नुकसान हुआ था या नहीं; प्रत्यर्थी यह स्थापित करने के लिए न्यायालय के समक्ष सामग्री रखने के लिए बाध्य था कि नुकसान वास्तव में हुआ था; जिसने उसे निष्पादन बैंक गारंटी को लागू करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार, बैंक गारंटी को लागू किया जाना इस अधिकार क्षेत्र संबंधी तथ्य पर केंद्रित था।

(iii) इस मामले में पक्षकारों ने आठ (8) अनुबंध किए हैं; यद्यपि अलग-अलग स्थानों के लिए, जिसके संबंध में आठ (8) बैंक गारंटी प्रस्तुत की गई थी। बैंक गारंटी का कुल मूल्य 43 करोड़ रुपये था। यदि प्रत्यर्थी को सभी बैंक गारंटी भुनाने की अनुमति दी गई, तो याचिकाकर्ता व्यावहारिक रूप से दिवालिया हो जाएगा; जिससे उसके साथ गंभीर अन्याय होगा।

(iv) चूंकि नुकसान का तथ्य स्थापित नहीं किया गया था, इसलिए बैंक गारंटी लागू किया जाना धोखाधड़ीपूर्ण था।

(v) अनुबंध के निष्पादन में बाधाएं (याचिका में विज्ञापित), पूरी तरह से प्रत्यर्थी के ज़िम्मेदार होने के कारण, याचिकाकर्ता के पक्ष में विशेष अधिकार

उत्पन्न करती हैं; जो बैंक गारंटी के नकदीकरण पर रोक लगाने का एक और कारण था।

5.1 अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में, श्री सुंदरम ने निम्नलिखित निर्णय ***हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एवं अन्य बनाम सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड 2006 (आई) एडी (दिल्ली) 466 और स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य 200 (2013) डीएलटी 283 (डीबी)*** पर भरोसा किया:

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए विद्वान एएसजी श्री मेहरा ने तर्क दिया कि व्यादेश देने के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता का मामला बिना शर्त बैंक गारंटी के व्यादेश के अनुदान के लिए न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए तीन अपवादों में से किसी के भीतर नहीं आता है।

6.1 श्री मेहरा ने इस ओर से बैंक गारंटी की शर्तों और 23.10.2013 दिनांकित (बैंक गारंटी) लागू करने के पत्र पर भरोसा किया। यह उनका निवेदन था कि (बैंक गारंटी) लागू करने का पत्र इस तथ्य को दर्शाता है कि याचिकाकर्ता ने पक्षों के बीच प्राप्त समझौते के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है, और इस तरह के उल्लंघन के कारण, प्रत्यर्थी को होने वाला नुकसान/क्षति, जारी किए गए बैंक गारंटी के मूल्य से अधिक होगी।

6.2 श्री मेहरा का तर्क था कि अनुबंध के कुल मूल्य, जो कि 135 करोड़ रुपये (लगभग) के आसपास था, के एवज़ में याचिकाकर्ता ने केवल 12.65% राशि का काम पूरा किया था। वास्तव में, उन्होंने न्यायालय के ध्यान में लाया कि निविदा आमंत्रित करने वाली एक नई अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें अनुबंध का मूल्य 141 करोड़ रुपये (लगभग) दर्शाया गया था, जो कि पक्षों के बीच निष्पादित अनुबंध के मूल्य से कम से कम 13 करोड़ रुपये (लगभग) अधिक था। दूसरे शब्दों में, श्री मेहरा ने यह बताने की कोशिश की कि, वास्तव में (जैसा कि स्पष्ट था), नुकसान पहले ही हो चुका था और, इस बात की पूरी संभावना थी कि यह ऊपर बताए गए मूल्यों के अंतर से कहीं अधिक हो।

6.3 किसी भी स्थिति में, श्री मेहरा के अनुसार, गारंटी की शर्तों के अनुसार प्रत्यर्थी को केवल यह कहना था कि उल्लंघन हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप नुकसान हुआ था या होने की संभावना थी। इसके अलावा, श्री मेहरा का तर्क था कि जीसीसी के खंड 47 और 48 और खंड 60 के पहले प्रावधान पर भरोसा करना गलत था, क्योंकि इनमें से किसी भी खंड का उल्लेख बैंक गारंटी में नहीं किया गया था।

6.4 अपनी प्रस्तुति के समर्थन में, श्री मेहरा ने मू.वि.या. सं. 1005/2013 में दिनांकित 04.10.2013 के समान पक्षों के बीच दिए गए निर्णय पर भरोसा किया। इस निर्णय के आधार पर, श्री मेहरा ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने निर्णय सुनाया था, (एक बैंक गारंटी के संबंध में जिसमें समान शर्तें थीं), कि

जहां लाभार्थी संभावित नुकसान के दायरे में था, जो उसके कारण हो सकता था, नुकसान की मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह किसी भी स्थिति में बैंक गारंटी की एक शर्त नहीं थी।

<u>कारण</u>

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, श्री सुंदरम द्वारा मेरे सामने प्रस्तुत किये गए तर्क, एक सूक्ति का उपयोग किया जाए तो, वास्तव में, एक नई बोतल में पुरानी शराब की प्रकृति के हैं। हालांकि, मुझे यह कहना होगा कि श्री सुंदरम ने मू.वि.या संख्या 1097/2013 में मेरे द्वारा, समान पक्षकारों के मध्य, दिनांक 01.11.2013 को दिए गए निर्णय में, इस तथ्य पर जोर देते हुए, अंतर करने की कोशिश की, कि उस निर्णय में नुकसान के तथ्य के संबंध में तर्क पर विचार नहीं किया गया था।

8. इसलिए, मुझे श्री सुंदरम के इस तर्क पर विचार करने दें, जिसके आधार पर वे व्यक्त करते प्रतीत होते हैं कि बैंक गारंटी, जो अन्यथा बिना शर्त है, एक सशर्त बैंक गारंटी में रूपांतरित हो गई है। इस उद्देश्य के लिए, सुविधा के लिए, बैंक गारंटी का प्रासंगिक हिस्सा, जिस पर श्री सुंदरम द्वारा निर्भरता रखी गई है, निम्नानुसार उद्धृत है:

> "....हम आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, <u>सरकार की ओर से किसी भी मांग पर इस गारंटी के तहत देय और भुगतान योग्य राशि</u>

> <u>का भुगतान करने का एतद् द्वारा वचन देते हैं, जिसमें कहा गया हो कि ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध में निहित किसी भी नियम या शर्त के उल्लंघन के कारण या ठेकेदार द्वारा उक्त अनुबंध को निष्पादित करने में विफलता के कारण दावा की गई राशि सरकार को हुई या होने वाली या हो चुकी हानि या क्षति के कारण देय है।</u> बैंक से की गई ऐसी कोई भी मांग इस गारंटी के तहत बैंक द्वारा देय और भुगतान योग्य राशि के संबंध में निर्णायक होगी। हालांकि, इस गारंटी के तहत हमारी देयता 6,76,69,100 रुपये (छह करोड़ छिहत्तर लाख उनसठ हजार एक सौ रुपये मात्र) से अधिक नहीं होगी।
>
> (मेरे द्वारा ज़ोर दिया गया)

8.1 बैंक गारंटी के उपरोक्त उद्धरण को पढ़ने से पता चलता है कि संबंधित बैंक, जिसने बैंक गारंटी प्रस्तुत की है, को केवल मांग पर, लाभार्थी को, यानी प्रत्यर्थी को, गारंटी के तहत देय और देय राशियों का भुगतान करना आवश्यक है।

8.2 इसलिए, यह जांचना आवश्यक है कि मांग किस तरीके से की जानी चाहिए। बैंक गारंटी की शर्तों के अनुसार, लाभार्थी की मांग में यह बताना आवश्यक है कि ठेकेदार द्वारा समझौते में निहित किसी भी नियम और शर्त के उल्लंघन के कारण या ठेकेदार द्वारा उक्त समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता के कारण, दावा की गई राशि उसे हुई हानि या क्षति या उसके कारण होने वाली क्षति के कारण देय हो गई है।

9. पूर्वोक्त के आलोक में, अगला चरण तार्किक रूप से (बैंक गारंटी) लागू करने के पत्र की प्रासंगिक सामग्री की जांच करना होगा। इसलिए, दिनांक 23.10.2013 के पत्र के प्रासंगिक भाग, यानी पैराग्राफ 5 और 6, नीचे उद्धृत किए गए हैं।

> ".....5. और चूंकि ठेकेदार द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया गया है और ऐसे उल्लंघन के कारण सरकार को नुकसान/क्षति होगी जो मुख्यालय महानिदेशक एमएपी के अनुमान के अनुसार उक्त बैंक गारंटी बॉंड के मूल्य से अधिक होगी।
>
> 6. मैं, भारत के राष्ट्रपति की ओर से, आपको उपरोक्त बैंक गारंटी बांड के विरुद्ध 6,76,69,100/- (छह करोड़ छिहत्तर लाख उनसठ हजार एक सौ मात्र) की राशि की मांग का यह नोटिस भेज रहा हूँ, जो सरकार को होने वाली हानि/क्षति के एवज़ में है।"

9.1 उपर्युक्त उद्धरण को पढ़ने से पता चलता है कि प्रत्यर्थी ने सबसे पहले कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। दूसरा, उल्लंघन के परिणामस्वरूप नुकसान या क्षति होगी। अंत में, प्रत्यर्थी का अनुमान है कि नुकसान/क्षति जारी बैंक गारंटी के मूल्य से अधिक होगी।

9.2 जैसा कि मैंने बैंक गारंटी की शर्तों को पढ़ा, इसमें दो परिदृश्यों की परिकल्पना की गई है। पहला, जहां लाभार्थी को विपक्षी द्वारा किए गए उल्लंघन के कारण न केवल क्षति हुई होगी, बल्कि नुकसान की मात्रा भी निर्धारित की गई होगी, उदाहरण के लिए, जहां उसने क्षति होने की तारीख पर या उसके

तुरंत बाद लेकिन बैंक गारंटी को लागू करने से पहले जोखिम खरीद अनुबंध में प्रवेश किया था। दूसरा, जो वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाली स्थिति है, जहां उल्लंघन हुआ है जिसके परिणामस्वरूप क्षति हुई है, हालांकि नुकसान की मात्रा निर्धारित करना संभव नहीं था, क्योंकि अगला चरण, जो एक नए अनुबंध का निष्पादन है, अभी तक पूरा नहीं हुआ था। वर्तमान मामले के तथ्यों में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अनुबंध के निष्पादन में देरी हुई है। वास्तव में पक्षों के बीच जो विवाद है, वह यह है कि अनुबंध के निष्पादन में हुई देरी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सवाल यह है कि देरी किसके कारण हुई है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि प्रत्यर्थी के अनुसार, उल्लंघन हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप क्षति हुई है, जिसकी मात्रा प्रत्यर्थी अभी तक निर्धारित नहीं कर पाया है। इसलिए, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बैंक गारंटी के संदर्भ में, (बैंक गारंटी) लागू करने का पत्र उस हानि/क्षति की बात करता है, जो उल्लंघन के कारण उसे होगी, जिसका अनुमान बैंक गारंटी के मूल्य से अधिक है। इस प्रकार, बैंक गारंटी कानूनी क्षति और उस क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की मात्रा के बीच अंतर करती है, जब वह उस हानि की बात करती है जो लाभार्थी को होगी या वहन करनी होगी, उस स्थिति के विपरीत, जहां पहले से हुई हानि या क्षति के रूप में राशि का दावा किया जाता है। यह बिल्कुल संभव है; (हालांकि किसी को यह स्वीकार करना चाहिए कि वर्तमान समय में यह एक दूर की संभावना है, क्योंकि सामग्री और श्रम की लागत हर दिन बढ़ रही है), कि एक नया अनुबंध मूल अनुबंध के मूल्य से कम मूल्य का हो

सकता है जिसका ठेकेदार द्वारा उल्लंघन किया गया था। ऐसी स्थिति में, अंत में, भले ही लाभार्थी को कानूनी क्षति हुई हो, वह मौद्रिक शर्तों में किसी भी क्षति के लिए हकदार नहीं हो सकता है, क्योंकि भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 73 और 74 के तहत क्षति अंततः प्रकृति में प्रतिपूरक है, जिसे पीड़ित पक्ष को उसी स्थिति में रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है जैसा कि वह तब होता जब अनुबंध विपरीत पक्ष द्वारा उनके बीच सहमत शर्तों के अनुसार निष्पादित किया गया होता। ऐसा इसलिए है, क्योंकि यह अभ्यास बैंक गारंटी को लागू किए जाने के चरण में नहीं किया जा सकता है, अर्थात, जहां पीड़ित पक्ष द्वारा एक नया अनुबंध निष्पादित नहीं किया गया है, या जहां सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए हैं; बैंक को बिना किसी आपत्ति के और केवल लाभार्थी की मांग पर भुगतान करने के लिए कहा जाता है।

9.3 यह कहना ठीक नहीं है कि बैंक गारंटी एक स्वतंत्र अनुबंध है। जिस बैंक ने ठेकेदार, अर्थात इस मामले में याचिकाकर्ता के कहने पर बैंक गारंटी प्रस्तुत की है, उसे ठेकेदार और लाभार्थी, अर्थात याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच किए गए अंतर्निहित या मुख्य अनुबंध की शर्तों पर ध्यान नहीं देना है।

9.4 इसलिए, श्री सुंदरम का यह तर्क कि जीसीसी के खंड 47 और 48 के प्रावधानों और खंड 60 के पहले परंतुक को देखना होगा, एक से अधिक कारणों से पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सबसे पहले, बैंक गारंटी में उक्त खंडों का कोई संदर्भ नहीं है। दूसरे, न्यायालय द्वारा जांच संबंधित बैंक के दृष्टिकोण से होनी

चाहिए जिसने बैंक गारंटी प्रदान की है और उससे स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। इसी कारण से धोखाधड़ी के अपवाद या अन्य अपवाद की जांच करते समय, जो यह है कि लागू किए जाने की कार्यवाही बैंक गारंटी के संदर्भ में है या नहीं, न्यायालय द्वारा अपनाए गए परीक्षण इस प्रकार हैं: क्या धोखाधड़ी "गंभीर" है? क्या यह बैंक को ज्ञात लाभार्थी की स्थापित धोखाधड़ी है? क्या नकदीकरण बैंक गारंटी की शर्तों के अनुरूप है? ऊपर उल्लिखित दो अपवादों के संबंध में, न्यायालय को बैंक के दृष्टिकोण से सामग्री की जांच करनी है। यदि कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो इससे बैंक पर अस्वीकार्य बोझ पड़ेगा और इसलिए, एक अर्थ में, वाणिज्यिक जगत शिथिल हो जाएगा, जो कि मुख्य कारण है कि न्यायालय आमतौर पर बैंक गारंटी के नकदीकरण पर रोक नहीं लगाते हैं, सिवाय इसके कि जहाँ परिस्थितियाँ ऊपर बताए गए अपवादों के अंतर्गत आती हैं। शायद एकमात्र क्षेत्र, जहाँ न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत सामग्री की जाँच कर सकता है, और उस अर्थ में बैंक से स्वतंत्र, वह है जहाँ पीड़ित पक्ष विशेष इक्विटी का मामला स्थापित करता है। इसलिए, श्री सुंदरम का तर्क कि इस विशेष मामले में न्यायालय को इस स्तर पर नुकसान के तथ्य की जाँच करने की आवश्यकता है, मेरे विचार में, एक ऐसा तर्क है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

10. जहाँ तक विशेष इक्विटी का सवाल है, मेरे सामने एकमात्र तर्क जो संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, वह यह है कि अनुबंध के निष्पादन में कई बाधाएँ थीं,

जो पूरी तरह से प्रत्यर्थी के कारण थीं। बैंक गारंटी से संबंधित निर्णयों का समग्र दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि न्यायालयों ने "विशेष इक्विटी" अभिव्यक्ति को "अपूरणीय क्षति" या "अपूरणीय अन्याय" जैसी अभिव्यक्तियों के साथ परस्पर रूप से इस्तेमाल किया है। मेरी राय में, "अपूरणीय क्षति" या "अपूरणीय अन्याय" अभिव्यक्ति को सटीकता के साथ परिभाषित करना मुश्किल है, क्योंकि यह प्रत्येक मामले में प्राप्त तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हालाँकि, मेरे विचार से, एक व्यापक परीक्षण यह होगा कि, क्या पीड़ित पक्ष को विपक्षी से बैंक गारंटी में दर्शाई गई राशियों को प्राप्त करना या वसूलना मुश्किल होगा, यदि पीड़ित पक्ष अंततः मुख्य कार्रवाई में सफल होता है, जिसे वह विपरीत पक्ष के खिलाफ शुरू कर सकता है। [देखें विनीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम एचसीएल इंफोसिस्टम्स लिमिटेड (2008) 1 एससीसी 544 पैराग्राफ 29 में पेज 553 पर]। यदि मैं वर्तमान मामले में उपरोक्त परीक्षण लागू करता हूं, तो मेरे विचार में, याचिकाकर्ता का मामला विशेष इक्विटी के दायरे में नहीं आता है।

10.1 मैंने वास्तव में ***डीएससी लिमिटेड*** मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया था, जिसमें कुछ हद तक समान स्थिति में विशेष इक्विटी के आधार पर निषेधाज्ञा प्रदान करने का मामला उठाया गया था। मैंने उस तर्क को खारिज कर दिया था। मामला खंड पीठ के समक्ष अपील में लाया गया था। अपील को इस प्रकार क्रमांकित किया गया था: एफएओ (ओएस) 374/2013। खंड पीठ ने

19.08.2013 के निर्णय द्वारा अपील को खारिज कर दिया। वास्तव में, उस निर्णय के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका पेश की गई थी, जिसे इस प्रकार क्रमांकित किया गया था: सिविल अपील संख्या 26796/2013। विशेष अनुमति याचिका को 27.08.2013 के आदेश द्वारा समयबद्ध तरीके से खारिज कर दिया गया था।

10.2 इस संदर्भ में, श्री सुंदरम का तर्क कि याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी के साथ कुल आठ अनुबंध किए थे और तदनुसार, 43 करोड़ रुपये की आठ बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी और सभी आठ बैंक गारंटी को भुनाने से याचिकाकर्ता बर्बाद हो जाएगा, एक ऐसा तर्क है जो निम्नलिखित बातों को नज़रअंदाज़ करता है। सबसे पहले, अनुबंध मूल्य के 5% की दर से (जो कि श्री सुंदरम ने मुझे प्रदान की गई दर है), 860 करोड़ रुपये (लगभग) के अनुबंधों के विरुद्ध 43 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी, कोई भी नियोक्ता ऐसे मूल्यों के अनुबंधों को अनावश्यक रूप से ख़तरे में नहीं डालना चाहता। मैं यह केवल मामले को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए कह रहा हूँ, सामान्य चेतावनी के साथ कि परीक्षण यह निर्धारित करेगा कि देरी के लिए कौन दोषी है। दूसरा, याचिकाकर्ता की वित्तीय स्थिति को दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है; मान लें कि कोई याचिकाकर्ता के वित्तीय मूल्य को देख सकता है। तीसरा, यह तर्क एक तरह से आत्म-पराजयकारी है, क्योंकि इसी कारण से बैंक गारंटी प्रदान की जाती है।

11. **डीएससी *लिमिटेड*** मामले में, मैंने इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय को अलग किया था, ***हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड*** के मामले में, वही अंतर वर्तमान मामले में भी सही होगा। ***हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड*** में बताए गए तथ्य यह दर्शाते हैं कि, उस मामले में जारी बैंक गारंटी को लागू करने की मांग की गई थी, भले ही बैंक गारंटी के लाभार्थी ने काम के पर्यास पूरा होने का प्रमाण पत्र जारी किया था; विवाद समीक्षा बोर्ड ने समय के विस्तार के लिए ठेकेदार के दावे के संबंध में उसके पक्ष में पर्यास राशि देने का निर्णय लिया था; और यह कि, आंतरिक समिति के विचार-विमर्श, जिसमें लाभार्थी कंपनी के सीएमडी शामिल थे, ने ठेकेदार के समर्थन में निष्कर्ष लौटाए थे। वास्तव में, बैंक गारंटी को प्रदर्शन अवधि की समाप्ति से ठीक एक दिन पहले लागू करने की मांग की गई थी। जैसा कि देखा जा सकता है, वर्तमान मामले में प्राप्त तथ्य पूरी तरह से अलग-अलग हैं।

12. जहां तक ***स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड*** के मामले में निर्णय का प्रश्न है, निर्णय में व्यक्त तथ्यों से पता चलता है कि खंड पीठ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने पर विचार कर रही थी। डीआरटी के आदेश को चुनौती निम्नलिखित परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में उत्पन्न हुई: न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता, यानी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (संक्षेप में एसटीसी) ने उस मामले में प्रत्यर्थी संख्या 3 के साथ गेहूं की खरीद के लिए

एक अनुबंध किया था। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अनुबंध का उचित प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए, एसटीसी ने एक प्रदर्शन गारंटी जारी करने पर जोर दिया, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 3 ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई)/प्रत्यर्थी संख्या 1 से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करके प्रदान किया। एसबीआई/प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने हितों की रक्षा के लिए काउंटर गारंटी मांगी थी, जो स्विस बैंक यानी यूबीएस एजी/प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा प्रदान की गई थी। चूंकि, एसटीसी और प्रत्यर्थी संख्या 3 के बीच विवाद उत्पन्न हुए, एसटीसी ने एसबीआई द्वारा प्रदान की गई बैंक गारंटी को लागू किया, जिसने उक्त राशि का भुगतान किया, बावजूद इसके कि यूबीएस एजी/प्रत्यर्थी संख्या 2 ने सूचित किया था कि काउंटर गारंटी के संदर्भ में भुगतान करने के लिए स्विस कोर्ट द्वारा उसे निषेधाज्ञा दी गई थी। स्विस कोर्ट के आदेश को स्विस फेडरल उच्चतम न्यायालय तक बरकरार रखा गया था। एसटीसी ने उन कार्यवाहियों का विरोध किया था। समानांतर रूप से, मुख्य अनुबंध के पक्षकारों यानी एसटीसी और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा मध्यस्थता का भी सहारा लिया गया था। मध्यस्थता पुरस्कार के तहत एसटीसी के पक्ष में एक निश्चित राशि प्रदान की गई थी। 3. चूंकि एसबीआई ने अपनी जेब से पैसे नहीं दिए थे, क्योंकि उसने एसटीसी को उसके द्वारा दी गई बैंक गारंटी के बदले भुगतान किया था, इसलिए उसने बकाया राशि की वसूली के लिए डीआरटी के समक्ष कार्यवाही शुरू की। उन कार्यवाहियों में न केवल एसटीसी को पक्षकार बनाया गया, बल्कि यूबीएस एजी/प्रत्यर्थी संख्या 2 और प्रत्यर्थी संख्या 3 को भी

प्रतिवादी बनाया गया। डीआरटी ने एसबीआई के पक्ष में और एसटीसी के खिलाफ वसूली प्रमाणपत्र जारी किया, जबकि यूबीएस एजी/प्रत्यर्थी संख्या 2 और प्रत्यर्थी संख्या 3 को "बरी कर दिया गया"। इसी पृष्ठभूमि में एसटीसी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका के माध्यम से डीआरटी के निर्णय पर आक्षेप किया। न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बैंक गारंटी को लागू किया जाना और उसके परिणामस्वरूप नकदीकरण धोखाधड़ीपूर्ण था, क्योंकि न केवल एसटीसी के खिलाफ पुरस्कार में निष्कर्ष थे, बल्कि स्विस न्यायालयों द्वारा एसटीसी के खिलाफ निष्कर्ष भी लौटाए गए थे। खंडपीठ ने यह भी कहा कि डीआरटी ने दर्ज किया था कि यूबीएस एजी/प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अनुबंध का प्रदर्शन किया गया था, और यदि कोई छोटा-मोटा बदलाव था, तो एसटीसी द्वारा बातचीत की जा सकती थी। एसटीसी द्वारा याचिका में उठाए गए मुद्दे, अन्य बातों के साथ-साथ, इस तथ्य से संबंधित थे कि डीआरटी के पास इस मामले में अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि एसटीसी पर एसबीआई का कोई "ऋण" नहीं था, और विदेशी न्यायालय के निर्णय को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि न केवल एसटीसी के पास माल था, बल्कि बैंक गारंटी भुनाने पर उससे प्राप्त धन भी उसके पास था और इस तरह उसने स्वयं को अनुचित रूप से समृद्ध किया। मेरे विचार में, खंड पीठ के निर्णय में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वर्तमान मामले में मौजूद तथ्यों से दूर-दूर तक मेल खाता हो। श्री सुंदरम का खंड पीठ के निर्णय पर भरोसा करना पूरी तरह से गलत है।

13. मेरे विचार में, याचिका में कोई गुणागुण नहीं है। हालाँकि, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे द्वारा ऊपर की गई कोई भी टिप्पणी प्रथमदृष्टया प्रकृति की है और यदि याचिकाकर्ता को मध्यस्थता कार्यवाही का सहारा लेना था, तो याचिका में व्यक्त किए गए विवादों के गुणागुण पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14. इन परिस्थितियों में, याचिका को रुपये की लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है। 25,000/-। लगाया गया खर्च एक सप्ताह के भीतर प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कर दिया जाएगा। संबंधित बैंक धनराशि को, जैसा कि जारी किए गए बैंक गारंटी में परिलक्षित होता है, प्रत्यर्थी को तुरंत प्रेषित करेगा।

15. 29.11.2013 पर अनुपालन के लिए विद्वान संयुक्त पंजीयक के समक्ष सूची बनाएँ।

राजीव शकधर, न्या.

18 नवंबर, 2013
केके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*